

#### **Caution Notice**

#### Attention to all Customers and the General Public

Dear Client,

It has come to our notice that some unknown individuals have been fraudulently using our Company name Angel One Ltd. & Blackrock to carry out scams and illicit activities through the social media application "Angel Guard" and collecting funds, offering returns on investment. We would like to emphasize that these individuals do not represent Angel One Limited or any of its affiliates/channel partners in any capacity. Furthermore, we also like to mention here that Angel One Limited has no association / strategic partnership with Blackrock in any capacity.

It has also been observed that these fraudsters have been reaching out to individuals, claiming to be representatives of our company Angel One Ltd, and offering false services, products, or investment opportunities. They may even provide fraudulent websites, documents, contact details, or mobile apps (resembling the same as Angel One Ltd.) on Android / iOS to trick their victims into believing their authenticity or association with Angel One Limited.

We would like to inform everyone that Angel One Limited has no involvement whatsoever in any such activities and we strongly condemn any fraudulent actions carried out in our Company name. We are a reputable Company committed to upholding the highest standards of integrity and professionalism in all our operations.

These fraudsters may contact unsuspecting individuals through various means, including phone calls, emails, or social media platforms, pretending to be representatives of Angel One Limited They may present false documentation, false investment plans, or provide misleading information in an attempt to deceive their victims.

This is to inform you that we have initiated necessary legal action including intimation to the law enforcement authorities.

We also deny any association/strategic partnership with Blackrock as mentioned in below sample articles published on social media/news media.

https://newspatrolling.com/blackrock-has-established-a-strategic-partnership-with-angelone-jointly-creating-a-new-chapter-in-the-clearing-and-settlement-by-broker-cbs-model/

<u>https://sccbuzz.in/blackrock-and-angelone-transform-cbs-model-in-pioneering-partnership/</u>

https://allmeaninginhindi.com/blackrock-has-established-a-strategic-partnership-with-angelone-jointly-creating/

https://marketbusiness.net/blackrock-has-established-a-strategic-partnership-with-angelone/

Refer following links for the company's social media presence:

https://www.angelone.in/

https://www.facebook.com/OfficialAngelOne

https://t.me/Official\_AngelOne

https://youtube.com/@angelone/ https://www.instagram.com/angelone/

https://www.linkedin.com/company/angelone/

## To protect yourself from falling victim to their scams, we advise the following precautions:

- Be cautious when providing personal information: Only provide sensitive personal and financial information to trusted sources and official channels of Angel One Ltd.
- Verify the legitimacy of any requests: If you receive any unexpected or suspicious communication claiming to be from Angel One Ltd., verify its authenticity by reaching out to our official channels using the contact information available on our official website.
- Beware of suspicious offers: Be wary of any offers or schemes that seem too good to be true. Always conduct thorough research and due diligence before engaging in any financial transactions or investments.
- Change your passwords regularly and use strong passwords that are difficult to predict. Do not share OTP / PIN with anyone.
- Be cautious while transferring funds to a third-party account.
- Make sure you keep your contact information up to date and always check for any suspicious activity in your accounts
- Report any fraudulent activity: If you have been contacted by someone
  fraudulently using the name of Angel One Ltd. or if you suspect any
  fraudulent activity, please report it immediately to the local authorities and
  inform us through our official channels.

Please remember that Angel One Ltd. takes your security and trust seriously and we remain dedicated & committed to providing our customers with reliable and legitimate services.

Thank you for your cooperation and assistance in preventing any further suspicious activities.

Regards, Team Angel One



हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजिज



हिंद रेक्टीफायर्स



भारतीय रेलवे से 200 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

₹ 561.4 पिछला बंद भाव ₹ 617.5 आज का बंद भाव महानगर गैस **1,512** 1,530 1,505

**3ईवी इंडस्ट्रीज में 31** करने के लिए समझौता ₹ 1,504.7 पिछला बंद भाव 2024 Feb Feb 26 27

प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल

₹ 1,512.0 आज का बंद भाव

गोल्डियम इंटरनैशनल



पावर मेक प्रोजेक्ट्स

5,222 5230 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 396 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला <sub>5180</sub> <sup>5130</sup> **₹ 5,208.1** पिछला बंद भाव 5080 **₹ 5,221.8** आज का बंद भाव

### संक्षेप में

### ताकेदा करेगी डेंगू के टीके का क्लीनिकल परीक्षण

भारत को जल्द ही जापान की दवा कंपनी ताकेदा डेंग का टीका क्युडेंगा मिल सकता है। कंपनी को हाल में स्थानीय क्लीनिकल परीक्षणों के लिए भारतीय नियामक से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। फिलहाल क्यूडेंगा यूरोप, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों के निजी बाजार में तथा अर्जेंटीना और ब्राजील में निजी और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के वास्ते बच्चों और वयस्कों के लिए उपलब्ध है। इस बीच ताकेदा ने डेंग् का टीका बनाने के लिए हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई (बीई) के साथ समझौता किया है। कंपनियों ने मंगलवार को बयान में कहा कि यह साझेदारी डेंगू बुखार के वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी साल 2030 तक डेंगू के मामलों में मृत्यु दर खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। कंपनी ने कहा कि यह साझेदारी टीके की स्थायी वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएगी। बायोलॉजिकल ई अपनी उत्पादन क्षमता को संभावित रूप से सालाना पांच करोड़ ख़ुराक तक पहुंचाएगी।

### जायडस लाइफ. की पुनर्खरीद पेशकश 29 से

जायडस लाइफसाइंसेज की 1,005 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 600 करोड़ रुपये में 59.7 लाख शेयर पुनर्खरीद की पेशकश 29 फरवरी को खुलेगी। जायडस लाइफसाइंसेज ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सचना में कहा कि शेयर पुनर्खरीद पेशकश छह मार्च, 2024 को बंद हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि उसने 1,005 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 59,70,149 शेयरों की पुनर्खरीद का प्रस्ताव रखा है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.38 प्रतिशत बढ़कर 946.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

### जेएसडब्ल्यू एनर्जी को मिली सौर परियोजना

जेएसडब्ल्यू एनर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र की एसजेवीएन लिमिटेड से 700 मेगावॉट की सौर परियोजना मिली है। जेएसडब्ल्यू ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस परियोजना को इसकी अनुषंगी कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड ( जेएसडब्ल्य नियो ) द्वारा 1,500 मेगावॉट (अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र) आईएसटीएस-संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आमंत्रित टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में हासिल किया गया है। कंपनी ने कहा कि एसजेवीएन लिमिटेड से 700 मेगावाट क्षमता के अधिकार पत्र (एलओए) के बाद, कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 11.0 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हो गई, जिसमें 1.4 गीगावाट सौर क्षमता है।

### एक्सेलरेट ने 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए

कानुनी अनुपालन सेवा प्रदाता अपराजिता की मूल कंपनी सिंगापुर की एक्सेलरेट ने निजी इक्विटी फर्म फेडरेटेड हर्मीस और अन्य से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक्सीलरेट के सह-संस्थापक मधुजीत चिमनी ने बयान में कहा कि सबसे ज्यादा निवेश वैश्विक निजी इक्विटी निवेशक फेडरेटेड हर्मीस से जुटाया गया। इसके पास दिसंबर, 2023 तक 757 अरब डॉलर की प्रबंधन अधीन संपत्ति थी।

## 'लीज अधिसूचना से विमानन कंपनियां अनिश्चितता में

दीपक पटेल नई दिल्ली, 27 फरवरी

🛮 यर इंडिया के जनरल काउंसिल जुबिन मसानी ने मंगलवार को कहा कि सरकार की 3 अक्टबर की अधिसूचना के कारण भारतीय विमानन कंपनियां अनिश्चितता में फंसी हुई हैं। इस अधिसूचना में विमान और उनके इंजनों से संबंधित सभी समझौतों को आईबीसी, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट अधिस्थगन अधिकारों से अलग रखा गया है।

गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के समक्ष दिवालिया आवेदन सौंपने के बाद 3 मई को परिचालन बंद कर दिया था। 10 मई को, पंचाट ने एयरलाइन की परिसंप त्तियों पर रोक लगा दी और इस वजह से पट्टादाताओं को विमानन कंपनी से अपने करीब 45 विमान पाने का दावा करने से रोक दिया गया। इस निर्णय ने पट्टादाताओं में गहरा असंतोष पैदा हो

इसलिए, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल 3 अक्टबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई एयरलाइन अब



मंत्रालय ने पिछले साल 3 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी

दिवालिया प्रक्रिया में जाती है तो वह धारा 14 का हवाला देकर अदालत से पट्टेदारों को अपने विमानों को पुनः प्राप्त करने से रोकने के लिए नहीं कह सकती है।

एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्रोथ फ्रंटियर्स इंडिया 2024 में बोलते हुए मसानी ने कहा, 'मैं पट्टादाताओं को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्षेत्रा

धिकार संबंधित जोखिम वह नहीं है जो वे महसूस करते हैं, खासकर 3 अक्टूबर की इस अधिसचना के बाद। मेरा मानना है कि पट्टादाता अब ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरलाइन पहले की तुलना में ज्यादा खराब हालत में हैं। इसलिए हम वाकई अनिश्चितता के बीच फंसे हए हैं।'

उन्होंने कहा, 'यदि पट्टादाताओं को क्षेत्राधिकार जोखिम से अवगत नहीं कराया जाता है तो क्रेडिट जोखिम का भी सवाल है। हमारे पास एएए क्रेडिट रेटिंग वाली एयरलाइन हैं जिन्हें अपने अनुबं ध संबंधित दायित्वों पर कभी विफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्हें बड़ी मदद मिल सकेगी।'

वर्ष 2008 में, भारत ने केप टाउन कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे। यह संधि पट्टादाताओं को अपने विमान वापस पाने. उनके जोखिम दर करने के उपाय मुहैया कराती है। पट्टादाता भारत से इस संधि को लागू करने के लिए एक संसदीय विधेयक पारित करने का आग्रह कर रहे हैं, जो दिवाला कानूनों पर सीटीसी को प्राथमिकता देगा। 3 अक्टबर की अधिसुचना के साथ, भारत सरकार ने इस संधि को अपनाया। हालां कि मसानी ने इसमें समस्याओं का संकेत

सीटीसी के तहत विमान को पट्टादाता द्वारा पुनः प्राप्त करने से पहले एयरलाइन को 60 दिन की 'प्रतीक्षा अवधि' दी जानी होती है, लेकिन 3 अक्टूबर की अ धिसचना के तहत ऐसा कोई प्रावधान

## भारतीय विमानन फर्मों में हिस्सेदारी पर नजर नहीं: एयरएशिया

चेन्नई, २७ फरवरी

मलेशिया के विमानन क्षेत्र के एयरएशिया समूह ने आज कहा कि वर्तमान में वह किसी भी भारतीय विमानन कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करने को उत्सुक नहीं है तथा समूह का इरादा आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का है। एयरएशिया समूह द्वारा टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को अपनी पुरी हिस्सेदारी बेचकर एयरएशिया इंडिया से बाहर निकलने के लगभग दो साल बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

एयरएशिया के मुख्य हवाई अड्डा और ग्राहक अनुभव अधिकारी केसवन शिवानंदन ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बिजनेस स्टैंडर्ड के सवाल का जवाब देते हए कहा 'वर्तमान में हम भारत में किसी अन्य विमानन कंपनी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। भारत में कुछ भी नहीं देख रहे हैं। भारत में विनिवेश करना एक रणनीतिक फैसला था। हम अपने मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो आसियान है। हम इस क्षेत्र में और



अधिक उडानें शुरू करने तथा आसियान से भारत जैसे अन्य देशों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं'

दिनया की यह 13वीं सबसे बडी विमानन कंपनी वर्तमान में कुआलालंपुर और बैंकॉक से 14 भारतीय शहरों से जुड़ी हुई है। शिवानंदन ने कहा 'हम अब मध्य और छोटे शहरों पर ध्यान दे रहे हैं। अब 14 शहरों से हम साल 2024 के अंत तक 20 शहरों तक विस्तार करना चाहते हैं।'

फिलहाल कंपनी के कुल राजस्व में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत है। इसके अलावा भारत से जाने वाली उडानों में एयरएशिया के मामले में 90 प्रतिशत का लोड फैक्टर रहता है।

## वोल्वो की नजर ईवी से

अंजलि सिंह मुंबई, 27 फरवरी

वोल्वो कार इंडिया ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2024 में उसकी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का योगदान एक-तिहाई होगा। 2023 में लक्जरी कार निर्माता ने 2,423 वाहनों की बिक्री की थी। 2023 में उसकी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान 28

ईवी मॉडलों एक्ससी40 और सी40 ने 510 और 180 वाहनों की बिक्री दर्ज की थी। वोल्वो ने वर्ष 2030 तक संपर्ण रूप से इलेक्टिक कार निर्माता बनने का लक्ष्य रखा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लक्जरी सेगमेंट में वोल्वो 24 प्रतिशत भागीदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। बीएमडब्ल्यू इस सेगमेंट में पहले स्थान पर है। वर्ष 2023 में वोल्वो कार इंडिया ने कुल 2,423 वाहन बेचे, जिनमें 690 ईवी थे। इससे सालाना आधार पर 31 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। वोल्वो ने वर्ष 2025 तक

भारतीय बाजार में दो अन्य इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की



अपनी योजनाओं की भी पुष्टि की है। नए मॉडलों में ईएक्स30 और ईएक्स90 इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हैं जिन्हें अगले साल पेश किया जाएगा।

वोल्वो इंडिया की प्रबंध निदेशक ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को मीडिया के साथ बातचीत में कंपनी की ईवी योजनाओं के विस्तार की पु ष्टि की। उन्होंने कहा, 'वोल्वो के लिए 2030 तक विजन बेहद स्पष्ट है। वोल्वो इलेक्टिक कार कंपनी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यह विशेष रूप से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) पर केंद्रित है।' कंपनी इस समय 25 आउटलेटों के साथ परिचालन करती है और उसने अपनी सेवाओं का विस्तार करने पर जोर दिया है।

## स्कोडा को अपनी नई कॉम्पेक्ट एक-तिहाई बिक्री पर एसयूवी से उम्मीद

मुंबई, 27 फरवरी

स्कोडा ऑटो इंडिया का इरादा साल 2026 तक भारत में सालाना 1,00,000 गाड़ियों की बिक्री करने का है। इसके लिए कंपनी साल 2025 की पहली छमाही तक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) श्रेणी में नई कार लाने वाली हैं। यूरोप की इस प्रमुख कार कंपनी की नजर साल 2030 तक भारतीय यात्री वाहन बाजार में फोक्सवैगन परिवार के ब्रांडों की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने पर है। स्कोडा इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 48,000 गाड़ियों का

उत्पादन किया था। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में निर्मित यह कार मारुति ब्रेजा, ह्युंडै वेन्यू और किया सोनेट से टक्कर लेगी तथा इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी होगी। स्कोडा इस कार को ऑस्ट्रेलिया, न्यजीलैंड और आसियान जैसे देशों के राइट-हैंड-ड्राइव बाजारों में भी निर्यात करेगी।

बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड



संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक पेट्र जनेबा फोटो : कमलेश पेडणेकर

पिछले साल कुल बाजार (यात्री वाहन बाजार ) में कॉम्पैक्ट एसयवी की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत थी और इसलिए स्कोडा इस श्रेणी से चुक नहीं सकती। जनेबा ने कहा 'हमारी नजर संख्या पर है और इसलिए हमारा मल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी होगा। इस कार की प्रतिस्पर्धी ब्रेजा, वेन्यू और सोनेट हैं और हम अपनी कार की कीमत प्रतिस्पर्धी रखेंगे।' इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ भारत में स्कोडा की बाजार संभावना काफी बढ़ जाएगी।

जनेबा ने कहा कि फिलहाल हमारा बाजार (कल यात्री वाहन

निदेशक पेट्र जनेबा ने कहा कि बाजार का) 27 प्रतिशत या उससे कम है और इस कार के जुड़ने से यह कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए हम भारत में सभी नए कार खरीदारों में से 80 प्रतिशत हासिल करने में सक्षम होंगे। आगामी कॉम्पैक्ट एसयवी एमक्यूबी-ए०-इन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे विशेष रूप से भारत के लिए विकसित किया गया है। कुशक और यह सब-कॉम्पैक्ट सैडान यही प्लेटफॉर्म साझा करती हैं। जनेबा ने कहा कि इस कार का व्हील-बेस कुछ छोटा होगा और इसमें प्रतिस्पर्धी कारों की तुलना में

## 'पतंजलि ने पूरे देश को किया गुमराह'

पृष्ट १ का शेष

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने भ्रामक दावों वाला एक और विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 'शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन देने की आपकी हिम्मत हो गई! और आप हमेशा के लिए राहत मिलने का विज्ञापन दे रहे हैं। हमेशा के लिए राहत से आपका क्या मतलब है ? क्या यह इलाज है ? हम बहुत, बहुत सख्त आदेश देने जा रहे हैं। आप अदालत को चुनौती दे रहे हैं।

दोपहर में आईएमए की तरफ से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि रामदेन ने अदालत की पिछली सुनवाई के बाद नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि रक्तचाप का इलाज 'एलोपैथी द्वारा फैलाया जा रहा झठ' है। पटवालिया ने कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश के अगले दिन ही वह कॉन्फ्रेंस की थी। न्यायमूर्ति अमानुल्ला ने कहा कि पहली नजर में अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है और रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण को नोटिस भेजा जाना चाहिए। इस पर पतंजलि की ओर से आए वरिष्ठ वकील विपिन सांघी ने कहा, 'जहां तक बाबा रामदेव की बात है तो वह संन्यासी हैं।' जवाब में न्यायाधीश ने कहा, 'कौन क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। पहली नजर में देखने पर उल्लंघन दिखता है।' पीठ कंपनी के विज्ञापनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था मगर पतंजलि के पैरोकार सांघी ने दलील दी कि कंपनी टूथपेस्ट जैसे उत्पाद भी बनाती है और पूरी तरह रोक लगाने का असर उसके कारोबार पर पड़ेगा।यह सुनकर अदालत ने कहा कि प्रतिबंध का आदेश औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में बताई गई दवाओं के विज्ञापनों पर लागु होगा।

## कंट्रोलएस चेन्नई डेटा सेंटर पार्क में करेगी बड़ा निवेश

एशिया की सबसे बड़ी रेटिंग-4 डेटासेंटर ऑपरेटर कंट्रोलएस डेटासेंटर्स ने चेन्नई में अपने आगामी डेंटासेंटर पार्क को शुरू किया है। भारत में मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और बेंगलूरु के बाद यह कंपनी का पांचवां डीसी कैम्पस होगा। कंट्रोलएस डेंटासेंटर्स अपने चेन्नई डेंटासेंटर पार्क में विभिन्न चरणों में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

कंपनी को इस पार्क से करीब 500 प्रत्यक्ष और 900 अप्रत्यक्ष नौकरियां निकलने की उम्मीद है। अंबातर औद्योगिक इलाके में स्थित इस परिसर में दो डेटासेंटर इमारतें शामिल होंगी, जिनका संयुक्त रूप से बिल्ट-अप एरिया करीब 10 लाख वर्ग फुट और क्षमता 72 मेगावॉट आईटी लोड की क्षमता होगी। पहले डेटासेंटर (चेन्नई डीसी1) की बुकिंग पूरी हो गई है। बीएस

#### ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

#### **PUBLIC NOTICE**

This is to inform that, Angel guard application on play store/IOS is wrongfully and deceptively using the brand name and logo of Angel One Limited to deceive the general public in believing it to be associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited does not have any association and/or relation, directly or indirectly with "Angel Guard" application in any capacity

Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or consequence of dealing with Angel Guard application. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility. For ANGEL ONE LTD

Authorized Signatory

Date: 28.02.2024

## छोटे-मझोले कारोबारियों के लिए जोहो लेकर आई 'जक्या'

आशुतोष मिश्रा नई दिल्ली, 27 फरवरी

सॉफ्टवेयर-एज-ए-सॉल्युशंस (सास) कंपनी जोहो ने नए कारोबारी अनुभाग 'जक्या' का ऐलान किया है। इसके तहत कंपनी छोटी और मझोले खुदरा दुकानदारों के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) समाधान पेश करेगी।

जक्या के चीफ इवेंजलिस्ट जयगोपाल धरानिकल ने कहा कि चूंकि उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी का रुख कर रहे हैं, इसलिए ऐसे खदरा विक्रेताओं के बीच डिजिटल समाधानों की मांग बढ रही है, जो प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं। अलबत्ता बाजार के मौजूदा समाधानों में या तो खुदरा विक्रेताओं को उनके रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए जरूरी सविधाओं का अभाव है या वे ऐसे परंपरागत सॉफ्टवेयर हैं, जो जटिल, कठिन हैं और जिन्हें सॉफ्टवेयर-एज-ए-सॉल्यूशंस कंपनी जोहो ने नए कारोबारी अनुभाग 'जक्या' का ऐलान किया

सीखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जक्या इस्तेमाल में आसान समाधान की पेशकश करते हुए इस अंतर को पाटता है। इसे जल्दी से तैनात किया जा सकता है, जिससे छोटे कारोबारों के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने की बाधा कम हो जाती है।

जक्या की कीमत प्रति माह 649 रुपये है। यह तमिल, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, मराठी और गुजराती सहित 10 भारतीय भाषाओं में छोटे और मझोले कारोबारों को स्टॉक प्रबंधन. ओम्नीचैनल बिक्री और अन्य बैक-ऑफिस काम-काज के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करेगा।

## मार्लैब्स इस साल 500 कर्मचारी शामिल करेगी

आयुष्मान बरुआ बेंगलूरु, 27 फरवरी

अमेरिका की आईटी कंपनी मार्लैंब्स को भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा से उम्मीद है और इस साल देश में लगभग 500 लोगों को काम पर रखने की योजना बना रही है। उसका इरादा अगले तीन साल में अपना राजस्व दोगुना करने का है। भारत पहले से ही कंपनी का सबसे बड़ा प्रतिभा केंद्र है। इसके कुल कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत भारत में ही हैं।

मार्लेब्स के मुख्य कार्य अधिकारी थॉमस कॉलिन्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया 'हम अगले तीन साल में अपना राजस्व दोगुना करने की योजना बना रहे हैं। भारत में नियुक्तियां मुख्य रूप से डेटा इंजीनियरिंग, एआई और उत्पाद इंजीनियरिंग के कौशल से संबंधित रहेंगी।' उन्होंने कहा कि अब तक यह सबसे बड़ा प्रतिभा आधार है।हमारे शीर्ष कार्यकारी नेतृत्व का आधा हिस्सा बेंगलुरु में है।

भारत में बेंगलूरु के अलावा हम कोच्चि, मैसूर और पुणे में मौजूद हैं। मार्लेब्स का तीन कारोबारी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है - डेटा इंजीनियरिंग और एआई, डिजिटल उत्पाद इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। कंपनी के राजस्व में इनका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा रहता है।

## हैपिएस्ट माइंड्स ने बनाया 6 नए उद्योग क्षेत्रों का ढांचा

अंदर ज्यादा जगह होगी।

बेंगलूरु, 27 फरवरी

आईटी क्षेत्र की कंपनी हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजिज ने साल 2031 तक एक अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंचने की अपनी रणनीति के तहत छह नए उद्योग समुहों (आईजी) को शामिल करते हुए नया संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है। कंपनी ने साल 2023 में 17.8 करोड़ डॉलर का राजस्व जुटाया है, जो पिछले साल की तुलना में 30.7 प्रतिशत अधिक है।

ये छह उद्योग समूह हैं - औद्योगिक, विनिर्माण और ऊर्जा एवं बिजली: स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान; खुदरा, सीपीजी और लॉजिस्टिक; बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई); हाई-टेक और मीडिया एवं मनोरंजन तथा एडटेक।

हैपिएस्ट माइंड्स के कार्यकारी चेयरमैन अशोक सूता ने कहा कि इस नई संरचना में संभावनाएं बहुत अधिक है और यह नए विकास इंजनों का आधार बनेगी, जो हमें वैश्विक बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने



साल 2031 तक एक अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंचने का लक्ष्य

और साल 2031 तक एक अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंचने के हमारे दुष्टिकोण को साकार करने में सक्षम बनाएगी।'

प्रत्येक नए उद्योग समूह का नेतृत्व एक प्रमुख द्वारा किया जाएगा, जिसकी अपनी रणनीति, कारोबार योजना, विपणन, बिक्री, डोमेन क्षमता, संपूर्ण ग्राहक तथा लोगों का अनुभव होगा। कंपनी ने कहा कि प्रत्येक उद्योग समूह क्षेत्र में गहन डोमेन विशेषज्ञता, मौजूदा अकाउंट विकास के लिए विशेषज्ञ कारोबार विकास प्रबंधक और आंतरिक परामर्श क्षमताओं वाली समर्पित टीमें होंगी।

## **Analysts remain selective** about space-related stocks

Govt recently eased FDI norms for the sector

HARSHITA SINGH New Delhi, 27 February

ast week, the government relaxed foreign direct investment (FDI) norms for the space sector by allowing 100 per cent FDI in manufacture of components, systems or sub-systems for satellites, ground segments, and user segments. It also permitted 74 per cent FDI in satellite manufacturing and operation as well as satellite data products and 49 per cent in development of launch vehicles and spaceports.

Following this, stocks of related companies saw an uptick on the bourses. Among the lot, Mishra Dhatu Nigam, MTAR Technologies, Data Patterns, Astra Microwave Products, Centum Electronics, Walchandnagar Industries and Paras Defence have risen 4-25 per cent since the announcement on February 21, albeit with some intermittent profit-booking.

"The development is positive and will allow domestic players to gain access to advanced technologies and expertise due to foreign tie-ups. But given the current valuations and fundamentals, we suggest avoiding fresh buying while existing investors can stay put," said Sanjay Moorjani, research analyst, Samco Securities.

Most stocks in the defence and space sectors have been on a one-way rally in the last one year, giving handsome returns like 367 per cent, driven by the government's push for indigenisation of defence manufacturing.

Valuations wise, most are trading at price-to-equity (PE) multiples ranging between 50 and 100 times on a 12-month trailing basis, data from BSE shows. Apollo Micro Systems commands a PE of 152 times, among the highest.

Relaxing FDI norms, analysts believe, will help listed defence companies sharpen their focus on space as a revenue segment and improve scalability, which has remained limited for them.

"FDI norms relaxation will help companies sharpen focus on the space segment from hereon as it is a niche area that requires high research to match global standards. Many players were already involved in the Chandrayaan project but scalability has been limited as Isro has



How stocks in the space sector are performing vis-à-vis benchmark indices

(As on Feb 27)	Price in ₹	1-yr chg ( %)	
Apollo Micro Systems	141.4	379.2	
Walchandnagar Industries	263.6	361.6	
Avantel	115.5	342.8	
Taneja Aerospace & Aviation	459.3	295.9	
PTC Industries	8,600.0	249.6	
Centum Electronics	1,891.8	242.4	
Astra Microwave Products	638.1	144.4	
Sensex	73,095.2	23.3	
Nifty 50	22,198.4	27.6	
Compiled by BS Research Bureau			Sources: Bloomberg, exchange

remained their major customer. But with the easing in FDI, companies can now participate in global missions too. They can increase their revenue as scalability and customer base go up," said Kranthi Bathini, director, equity strategy at WealthMills Securities.

#### **Investment strategy**

While the Street seems bullish on these counters, analysts suggest that investors remain stock specific as the recent development alone should not be a trigger for fresh buying given the high valuations.

Bathini, for instance, suggests evaluating companies based on their specific research domains related to space activities and the level of expertise in them.

PTC Industries, Walchandnagar Industries, BEL, and HAL remain his top bets from the defence and aerospace themes. The first three companies were among several firms that had supplied crucial hardware for the Chandrayaan-3 mission.

HAL primarily caters to the Indian defence forces, but has been involved in space-related activities, partnering Isro for

various space missions.

Its cryogenic engine facility caters to rocket engine manufacturing for Isro and it has also supplied key infrastructure for the Gaganyaan mission.

Among other players operating in this segment, MTAR Technologies earned 5 per cent (₹23 crore) of its total revenue from the space segment in April-December 2023. Of its order book of ₹1,179 crore as on December 31, 2023, this vertical held 11 per cent share. The company, in its latest earnings' call, said it expects space and aerospace revenue to grow sharply to ₹150 crore in FY25 from the current base of ₹45 crore. Astra Microwave's revenue in 9MFY24 had a 4 per cent contribution from the space segment, while it has 11 per cent share in the total order book of ₹1,813 crore.

The company said it is increasing focus on the satellite space in a significant manner, especially in communication systems.

It has incorporated a new subsidiary to scale up space technology as it sees strong growth prospects in the space segment

#### **COMBATING FRAUDULENT LOAN APPS**

## Opt for apps that have partnered reputable regulated entities

The app must be featured on that entity's website and in RBI's whitelist

SANJAY KUMAR SINGH & KARTHIK JEROME

The Financial Stability and Development Council (FSDC) recently called for more measures to curb lending  $by \, unauthorised \, loan \, apps. \, While \, the \,$ regulators work on making the landscape safer for borrowers, the latter need to exercise caution.

#### Evolving modus operandi

The influx of unauthorised apps into Google Play Store has decreased significantly since the peak of 2019-20. "Now we only encounter three to five such apps on Google Play Store each week. Google and various agencies. including us, keep an eye on Play Store," says Sugandha Saxena, chief executive officer (CEO), Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE). She adds that complaints from association members' customers also help them identify rogue apps quickly and inform Google.

Fraudsters are now disguising their apps. "Some claim to be calculators, loan guides, etc. to bypass initial scrutiny. Once approved, they introduce the

lending feature," says Saxena. They increasingly use Instagram and Facebook, "They lure users with engaging content, then direct them to pages mimicking Play Store, and prompt them to download APK (Android Application Package) files," says Saxena.

#### **Dire consequences**

 $Borrowing from\, a\, fraudulent$ loan app subjects the borrower to a variety of risks. One is exorbitant interest rates and hidden fees. "Borrowers may find themselves trapped in a debt cycle due to interest rates as high as 100-200 per cent, hidden charges, and penalties," says Gaurav Jalan, founder and

CEO, mPokket. Some apps may collect a processing fee and disappear without disbursing the loan. Borrowers who do manage to secure a

loan may soon face aggressive and harassing calls demanding repayment,

#### HARASSED BY LENDERS? **STEPS YOU CAN TAKE**

■ Document all communication and evidence of harassment from unauthorised loan providers or recovery agents

■ File a legal complaint against them with the police and with relevant authorities like the RBI

■ Consider sending a cease and desist letter through a lawyer to stop unfair collection practices

■ Raise a complaint at https://cybercrime.gov.in or call 1930 for assistance

■ Contact the National Consumer Helpline (1800-11-4000) for guidance on consumer protection issues

often within a short timeframe. "Defaulting on payments could subject borrowers to constant harassment and threats," says Jalan.

Many fraudulent loan apps require access to borrowers' personal information stored on their phone's contacts, gallery, etc. Borrowers may soon find their privacy compromised as these apps resort to misuse of personal data. "If you are unable to

pay back the loan, they might send messages to your contacts to shame you," says Vishal Dhawan, chief financial planner, Plan Ahead Wealth Advisors.

#### Red flags to watch out for Be wary of an app that

MONEY asks for too much personal info. "Legitimate lenders will not ask for information beyond the basic know

your customer (KYC) details," says Jalan. If an app is poorly designed or unprofessional, it could be a signal that something is amiss. Remain sceptical of

unsolicited communications and links

promising quick loans. Watch out for apps that can be downloaded via links embedded within texts or emails.

 $Aggressive\,marketing\,tactics\,should$ also serve as a red flag. "Illegal apps might bombard you with calls or messages to pressurise you into taking action," says Jalan.

Demand for upfront payments or processing fees should also make you wary.

#### Do the due diligence

Before downloading an app, conduct thorough research on it. "The Reserve Bank of India (RBI) publishes a list of apps referred to as a whitelist. Stick to it," savs Dhawan.

Verify if the app has partnered with a regulated entity (RE), in accordance with the RBI's digital lending guidelines. "These guidelines require partnerships between a regulated entity and a digital lending app to be clearly listed on the RE's official website,"

says Saxena. Avoid apps that claim to have an association with an

unknown or suspicious RE. Check the app's number of downloads.

"This information will tell you whether it has been operational for long and if many people have used it," says Saxena. Reading user reviews and reports of

suspicious activities can provide insights into notential risks Review the permissions the app asks for. Jalan suggests granting access to

necessary information only. Download apps from Google and Apple app stores only. Ensure that interest rates and terms are fair and transparent. "The new RBI guidelines mandate

disclosing the annual percentage rate (APR), the key facts statement (KFS), terms and conditions, privacy policies, and so on. Additionally, they require upfront fee disclosure," says Jalan. Finally, after you have taken the loan,

ensure you receive detailed documentation outlining loan terms, repayment schedule, and other pertinent information

#### **ANGEL ONE LIMITED**

Regd. Off: 601, 6" Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

#### **PUBLIC NOTICE**

This is to inform that, Angel guard application on play store/IOS is wrongfully and deceptively using the brand name and logo of Angel One Limited to deceive the general public in believing it to be associated with Angel One Limited. Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited Guard" application in any capacity.

Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or consequence of dealing with Angel Guard application. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.

For ANGEL ONE LTD

Date: 28.02.2024

Authorized Signatory

## TENDER NOTICE NO. ACE (P&C): TN - 24: 23-24

[A] Civil: ACE(P&C)/Contracts/Civil/ E-261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 & 277/66 KV Repark, Mahika, Koterpur, Bhuteswar Phase 1, Lothds, Dudana, Raiya, Bhaktinagar, Sardargadh Agiyol, Dejrota, Chhotaudepur, Gota, Sudavad, Mordevi S/S & Chhatral Construction of Control Room Building, Foundations, Cable Trench, C'Wall RCC Road & Misc. civil works at (1) Repark under Anjar Circle, (2) 66 kV Mahika s/s, 66 KV Lothda s/s, 66 KV Raiya s/s, 66 KV Bhaktinagar under Gondal Circle (3) Kotarpur s/s, 66 KV Gota s/s under Nadiad Circle (4) 220 Kv Bhuteshwar . Phase-1 (5) 66 Kv Dudana s/s, 220 KV Sardargadh under Junagadh (6) 66 KV Agiyol s/s, Dejrota s/s under Himatnagar Circle (7) 66 KV Chhotaudepur under Jambuva Circle (8) 66 KV Sudavad under Amreli Circle (9) 66 KV Mordevi s/sunder Navasari Circle (10) 66 KV Chhatral s/s under Mehsana Circle

[B] S/S: ACE(P&C)/Contract/E-173/ARC/66 KV TR Transportation: Tender for Annual Rate Contract (ARC) for Dismantling Loading Unloading Transportation Dragging Erection, Testing && Commissioning of 66 kv Class (66/11 or 66/22 KV) Power Transforms up to 20 MVA at Various substation of GETCO.

[C] Line: ACE(P&C)/Contract/E-181,184,185, 187, 188, 189 & 191/ Uprating/ TL/ 400 KV, 220KV, 66 KV/S&E: EPC of (a) Establishment of 400kV SSP Chorania line by interconnection of 400kV SSP - Asoj line and 400kV Asoj Chorania line with Twin ACSR Moose conductor on turnkey basis. (b) Uprating of existing 66kv lines on tower and H frame by high ampacity conductor/ HTLS conductor of equivalent size and weight of ACSR Dog conductor on turn key basis for (1) 66KV Machiyla (400KV) - MalviyaPipariya Line 13.07Rkm (2) 66KV Bhingrad-Lathi Line 14.406Rkm (3) 66kV Dhasa(220KV)-Bhingrad Line 18.396 Rkm. (c) Uprating of existing 66kv lines on tower and H frame by high ampacity conductor/ HTLS conductor of equivalent size and weight of ACSR Dog conductor on turn key basis for (1) 66kv Savarkundla- Gadhakada line 13.864 Rkm (2) 66kV Gadhakada- Goradka line 9.334Rkm (3) 66kv Goradka-Vijapadi line: 6.798Rkm. (d) Uprating of existing 66kv lines on tower and H frame by high ampacity conductor/HTLS conductor of equivalent size and weight of ACSR Dog conductor on turn key basis for (1) 66kv Visavadar-Ratang line 24.85 Rkm.(2) 66kv Visavadar-Sarsai line 14.607 Rkm. (e) Uprating of existing 66kv lines on tower and H frame by high ampacity conductor/HTLS conductor of equivalent size and weight of ACSR Dog conductor on turn key basis for (1)66kV Junagadh-Tap prabhatpur line 02-18.093Rkm. (2)66kv Keshod-Motighasari line 1.317Rkm (3) 66kv Motighasari-Bhatsimroli line 9.864RKm (4) 66kv Keshod Divrana line 9.792Rkm (5) 66kv Keshod-Sondarda line 4.585Rkm. (f) Uprating of existing 66kv lines on tower and H frame by high ampacity conductor/HTLS conductor of equivalent size and weight of ACSR Dog conductor on turn key basis for (1) 66kv Keshod-Koylana line-8.249 Rkm (2) 66kv Keshod-Maliya line 16.232Rkm (3) 66kV Keshod-Mangrol line 20.338 Rkm. (g) 220kV D/C Morbi Shivlakha LILO of both circuits at 400kV Shivlakha (Mewasa) of with AL-59 (61/3.50) conductor & 48F OPGW on turnkey basis (17.441km) - under GEC-Ìl scheme

Above Tender are available on web-site www.getcogujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com & getcotender.nprocure.com (For view, download and on line tender submission).

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender Addl Chief Engineer (Procurement & Contracts) 27/02/2024

## CIN: L14101MH1945PLC256122

CIN: L14101MH1945PLU230122

Registered Office: Marathon Innova, A Wing, 7th Floor, Off G.K. Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 **Board No.**: +91 4089 6100, **Fax No.**: +91 4089 6199 **Email**: cs@asigroup.co.in **Website**: www.asigroup.co.in

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration)Rules, 2014, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, Genera Circular No. 33/2020 dated 28th September 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated 05th May, 2022, Genera Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, and pursuant to other applicable laws and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), the approval of shareholders of Asi Industries Limited (the "Company") is being sought for Appointment of Mr. Arunanshu V. Agarwal (DIN: 00166400) as an Independent Director of the Company for a term of 5 (Five) Financial years effective from 10th February 2024 till 9th

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of Fursiant to the Work Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement on Tuesday 27th February, 2024 to all the Members of the Company, who have registered their mail address with the Company (in respect of the shares held in physical form) or with Depository Participant (in respect of the shares held in electronic form) as on Friday, 23rd February, 2024 i.e. the cut-off date. The Postal Ballot Notice will also be available on the on the website of the Company at https://www.asigroup.co.in/ the website of Link Intime India Private Limited at https://www.linkintime.co.in/ and website of BSE Limited at www.bseindia.com In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Shareholders can vote only through the remote e-voting process, physical copies of the Postal Ballo Notice and pre-paid business reply envelopes are not being sent to shareholders for this Postal Ballot. Shareholders whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 23rd March, 2024 will be considered for the purpose of e-voting and Voting rights of a Member or Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. Shareholders are requested to note that e-voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Thursday, 29th February, 2024 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Friday, 29th March, 2024. Members desiring to exercise their ote should cast their vote during this period, to be eligible for being considered Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, C-101, 247, Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400084 or e-mail at rnt.helpdesk@linkintime.co.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name & address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g.: Driving License, Election identity Card, Passport In support of the address of the member) .The instructions on the process of e-voting, including the manner in which Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through-voting, are provided in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 26th February, 2024 has appointed CS. Mr. Prabhat Maheshwari, (Membership No. FCS 2405/COP 1432) Partner of GMJ & Associates, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer for conducting the postal ballot through the evoting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director of the Company or any person authorized by the Board. The results shall be declared on or before Monday 1st April, 2024 and communicated to BSE Limited, NSE Limited Registrar and Share Transfer Agent and will also be displayed on the

Members feeing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43.

For ASI Industries Limited Manish P. Kakrai

Place: Mumbai Company Secretary & Compliance officer Date: 27th February 2024

#### M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking) Secretariat for Single Window System CIN: U51102MP1977SGC001392

21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India) Tel.: (91) 0755-2571830, 2575618, 3523505, E-mail: helpdesk@mpidc.co.in, Website: www.invest.mp.gov.in (Ref. No.: MPIDC/SWS-RFP/2024/NIT 164)

No. 52 /MPIDC/LM/AII RO/NIT-164

YOUR

Date: 26.02.2024

#### EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ALLOTMENT OF **INDUSTRIAL PLOTS THROUGH E-BIDDING**

Department of Industrial Policy and Investment Promotion (DIPIP), Government of Madhya Pradesh through MP Industrial Development Corporation Limited (A Govt. of M.P. Undertaking) has invited Online Tender cum Auction (E-forward auction) for allotment of available industrial plots in industrial area at Bhopal, Sehore, Rajgarh, Ratlam, Khargone, Burhanpur, Mandla, Jabalpur, Pandhurna, Rewa ,Singrauli and Dhar. The Process of which will start on the https:// www.mptenders.gov.in. from 01.03.2024.

The important conditions of e-bidding for the plot are as follows :-

- 1. The allotment of industrial plots will be governed by the provisions of "Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules 2019 (as amended 2022)".
- The application fee for each plot will be Rs 5000/- and GST amount will be payable separately. Application fee is non-refundable [Rule 11(ii)]
- In addition to the application fee, 25 % advance land premium amount of the prevailing rate on the date of application for the applied Plot will have to be deposited online, which will be adjustable at the time of allotment. [Rule 11(v)]
- The base price for e-bidding will be the sum of the Land Premium and Development Cost of the plot. Minimum bid amount over and above the base price Rs. Will be Rs 1,00,000/-
- To participate in e-bidding, it is necessary to have Class 3 Digital Signature. Detailed information about rules, procedure and plots etc. can also be viewed on MPIDC website https://invest.mp.gov.in/
- Corrigendum related to e-bidding process, if any, will not be published in the newspaper, it will be uploaded on https://mptenders.gov.in/portal.
- M.P. Madhyam/113998/2024

**CHIEF GENERAL MANAGER** 

# Companies, Insight Out

Companies, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> **Business Standard** Insight Out